



ISSN: 2395-7852



# International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM )

Volume 10, Issue 1, January 2023



INTERNATIONAL  
STANDARD  
SERIAL  
NUMBER  
INDIA

**IMPACT FACTOR: 6.551**

[www.ijarasem.com](http://www.ijarasem.com) | [ijarasem@gmail.com](mailto:ijarasem@gmail.com) | +91-9940572462 |

# एकल महिला एवं सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

नरेश कुमार जटिया

सह-आचार्य, समाजशास्त्र, स. ध. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर

सार

सामाजिक आर्थिक स्थिति (एसईएस) में न केवल आय बल्कि शैक्षिक उपलब्धि, वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिति और सामाजिक वर्ग की व्यक्तिपरक धारणाएँ भी शामिल हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति में जीवन की गुणवत्ता के साथ-साथ समाज के भीतर लोगों को मिलने वाले अवसर और विशेषाधिकार भी शामिल हो सकते हैं। गरीबी, विशेष रूप से, एक एकल कारक नहीं है, बल्कि कई शारीरिक और मनोसामाजिक तनावों द्वारा इसकी विशेषता है। इसके अलावा, एसईएस शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सहित जीवन काल में परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला का एक सुसंगत और विश्वसनीय भविष्यवक्ता है। इस प्रकार, एसईएस व्यवहार और सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है, जिसमें अनुसंधान, अभ्यास, शिक्षा और वकालत शामिल है।

एसईएस हमारे समाज को प्रभावित करता है

एसईएस हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहित समग्र मानव कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। कम एसईएस और इसके सहसंबंध, जैसे कम शैक्षिक उपलब्धि, गरीबी और खराब स्वास्थ्य, अंततः हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य वितरण, संसाधन वितरण और जीवन की गुणवत्ता में असमानताएँ संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व स्तर पर बढ़ रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की नींव पर अधिक ध्यान देने और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में गहरे अंतर को कम करने के प्रयासों से समाज को लाभ होता है।

एसईएस महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है

शोध से पता चलता है कि महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में एसईएस एक महत्वपूर्ण कारक है; विस्तार से, यह बच्चों और परिवारों के जीवन को दृढ़ता से प्रभावित करता है। महिलाओं के लिए धन और जीवन की गुणवत्ता में असमानताएँ लंबे समय से चली आ रही हैं और स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर मौजूद हैं। व्यवहार और सामाजिक विज्ञान पेशेवरों के पास उन रणनीतियों का अध्ययन और पहचान करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर इन असमानताओं को कम कर सकते हैं।

परिचय

आज संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से कहीं अधिक एकल महिलाएँ हैं।<sup>1</sup> साथ ही, सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के लिए क्रिश्चियन ई. वेलर और मिशेल ई. टॉल्सन के नए शोध से पता चलता है कि एकल महिलाओं को भी कुछ सबसे अधिक केंद्रित आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ता है।<sup>2</sup>

वेलर और टॉल्सन ने आर्थिक जोखिम को आय की अप्रत्याशित हानि के रूप में परिभाषित किया। गौरतलब है कि उन्होंने महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे प्रासंगिक प्रकार के आर्थिक जोखिमों की एक व्यापक अवधारणा को अपनाया, जिसमें अप्रत्याशित रूप से किसी और की देखभाल के लिए काम से छुट्टी लेना या देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण किसी की नौकरी खोना शामिल है। ये जोखिम इस तथ्य से और भी जटिल हो गए हैं कि आम तौर पर एकल महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में अप्रत्याशित आय हानि के खिलाफ कम बचाव होता है। एकल महिलाओं के पास आपातकाल की स्थिति में निकालने के लिए कम बचत होती है, साथ ही भविष्य के लिए घोंसले के अंडे के रूप में काम करने के लिए सेवानिवृत्ति बचत भी कम होती है।<sup>[1,2,3]</sup>

हालाँकि, आर्थिक जोखिमों से बचना अक्सर कठिन होता है। एकल महिलाओं को अप्रत्याशित देखभाल की ज़रूरतों या अप्रत्याशित नौकरी छूटने सहित जोखिमों का सामना करना पड़ता है। और श्रम बाजार में लैंगिक वेतन अंतर<sup>3</sup> और महिलाओं की आर्थिक असमानता के अन्य उपायों को देखते हुए इन चुनौतियों का सामना करना उनके लिए और भी कठिन है।<sup>4</sup> इस वास्तविकता को संबोधित करने के लिए, नीति निर्माताओं को सवैतनिक पारिवारिक और चिकित्सा अवकाश और विस्तारित बेरोजगारी बीमा जैसी नीतियाँ बनाकर सुरक्षा प्रणाली को अद्यतन करना चाहिए। ये सुरक्षा और बहुत कुछ यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाएँ और परिवार अनुचित आर्थिक संघर्षों का सामना किए बिना सामान्य जोखिमों को संभाल सकें, साथ ही महिलाएँ अपनी दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत को बेहतर ढंग से बनाए रख सकें और जमा कर सकें।



आर्थिक जोखिम क्या हैं और उनका सामना कौन करता है?

सभी लोगों को कुछ हद तक आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, लेकिन महिलाएं-विशेष रूप से एकल महिलाएं-कुछ उच्चतम स्तर के आर्थिक जोखिम का सामना करती हैं। आर्थिक जोखिम मोटे तौर पर आकस्मिक घटनाओं को संदर्भित करता है जो आर्थिक कल्याण में गिरावट का कारण बन सकता है। इस गिरावट को आय की हानि, बचत में गिरावट या ऋण में वृद्धि में मापा जा सकता है। आर्थिक जोखिम का प्रभाव तब तक अनुभव किया जाता है जब तक कोई व्यक्ति ऐसे जोखिमों के संपर्क में रहता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति के चरम मौसम की घटनाओं के संपर्क में आने से उन घटनाओं के प्रभावों को झेलने का जोखिम बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, बाढ़ एक आकस्मिक घटना है जो घरों और समुदायों को नष्ट कर सकती है। हालाँकि [4,5,6] बाढ़ की घटना का जोखिम समान रूप से नहीं फैलता है: बाढ़ के मैदान में रहने वाले लोगों के इस जोखिम के संपर्क में आने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो पानी के बड़े निकायों से दूर पहाड़ की चोटी पर रहते हैं।

इसलिए, आर्थिक जोखिम जोखिम उन आर्थिक जोखिमों की मात्रा निर्धारित करता है जिन्हें कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकता है। लोग स्टॉक, रियल एस्टेट और अपने स्वयं के व्यवसायों में निवेश करके जोखिम उठा सकते हैं। छंटनी या वेतन में कटौती की संभावना के कारण उन्हें अपनी नौकरियों के माध्यम से जोखिम का जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। और वे किसी और की देखभाल करके आर्थिक जोखिम का सामना कर सकते हैं - जैसे कि अप्रत्याशित रूप से एक बच्चे को आपातकालीन कक्ष में ले जाना या किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की देखभाल करना जो गिरने से उबर रहा है। जबकि हर किसी को कुछ हद तक आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ता है - उदाहरण के लिए, उनकी नौकरी या परिवार के माध्यम से - महिलाओं को पूर्ण भेदभाव और खंडित श्रम बाजारों के परिणामस्वरूप इन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के वर्चस्व वाले व्यवसायों में नियमित रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले व्यवसायों की तुलना में कम वेतन मिलता है।

हालाँकि, कुछ जोखिम उठाना अच्छा है। निवेश के मामले में, जोखिम उठाने से आर्थिक लाभ मिल सकता है। लेकिन महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम शेरों में निवेश करती हैं, जिससे शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाएं उच्च भुगतान से जुड़े कुछ जोखिमों से अनावश्यक रूप से दूर भागती हैं। परिणामस्वरूप, महिलाओं के पास बचत के निम्न स्तर, धन के <sup>5</sup> निचले स्तर, <sup>6</sup> और छोटे सेवानिवृत्ति खाते हैं। <sup>7</sup> महिलाओं की बचत और धन की कमी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पहले से ही असमान रूप से आर्थिक जोखिम का सामना कर रही हैं।

हालाँकि, कुछ हद तक विरोधाभासी रूप से, जब महिलाएं अपनी वित्तीय सुरक्षा में निवेश करती हैं - जैसे कि घर खरीदने या व्यवसाय शुरू करने के माध्यम से - तो अक्सर पुरुषों की तुलना में उनका जोखिम अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी संपत्ति कम विविध होती है: जबकि महिलाओं के पास सामान्य रूप से कम बचत होती है, उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आवास में होता है। <sup>8</sup> जब घर की कीमतें गिरती हैं, तो महिलाएं अपने घरों की कीमत [7,8,9] से अधिक का कर्ज तेजी से लेंगी और इस प्रकार फौजदारी में फंसने और अपनी कुल बचत का एक बड़ा हिस्सा खोने की अधिक संभावना होगी। इसी तरह, महिला व्यवसाय मालिकों को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। उनके पास खर्च करने के लिए अपनी स्वयं की पूंजी कम है और इसलिए उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जो आंशिक रूप से कम लाभप्रदता और कम व्यावसायिक वृद्धि में योगदान देता है। <sup>9</sup>

लेकिन केवल यह देखने से कि क्या महिलाएं स्टॉक, आवास और व्यवसाय में निवेश करती हैं, पहले से ही उनके जोखिम जोखिम के प्रमुख पहलुओं को नजरअंदाज कर देती हैं। आर्थिक जोखिम जोखिम में उन घटनाओं का सामना करना भी शामिल हो सकता है जो लोगों के काम और व्यक्तिगत जीवन में घटित हो सकती हैं - जैसे कि तलाक से गुजरना या परिवार के किसी सदस्य का बीमार पड़ना - जिसके लिए उन्हें कम आय के साथ रहना पड़ता है या बचत कम करनी पड़ती है। अधिकांश लोगों को आजीविका के लिए काम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि व्यवसाय धीमा हो तो सभी कार्यों में नौकरी से निकाले जाने या वेतन में कटौती का जोखिम शामिल होता है। एक आदर्श दुनिया में, कर्मचारियों को वेतन का त्याग किए बिना या नौकरी या करियर को पूरी तरह से छोड़े बिना अपने बीमार प्रियजनों की देखभाल के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। लेकिन ये अक्सर हकीकत से कोसों दूर होता है।

कई आर्थिक जोखिम सामान्य और अक्सर अपरिहार्य होते हैं। लोगों को नकारात्मक परिणामों के लिए तैयार होने और उन्हें सहने में मदद करने के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जाल के बिना, ये जोखिम दुर्भाग्य से बड़े पैमाने पर गिरावट का कारण बन सकते हैं। वित्तीय बाजार के जोखिमों के विपरीत, जो एक व्यक्ति अच्छे भुगतान की आशा में उठाना चुनता है, ये व्यक्तिगत जोखिम अपरिहार्य हैं जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचता है।

महिलाओं के आर्थिक जोखिम जोखिम और बचत पर नया शोध

नई सीएपी रिपोर्ट में आर्थिक जोखिमों की एक व्यापक अवधारणा शामिल है जो स्टॉक निवेश के माध्यम से वित्तीय बाजार जोखिम जोखिम से परे है। लेखक श्रम बाजार में जोखिम जोखिम की भी जांच करते हैं, जैसे कम वेतन, बेरोजगारी और देखभाल के लिए काम से अप्रत्याशित अवैतनिक छुट्टी। जब लोगों को नर्स या बाल देखभाल प्रदाता को काम पर रखने सहित अप्रत्याशित देखभाल खर्चों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो उच्च देखभाल जोखिम भी आय या बचत हानि का कारण बन सकता है।

वेलर और टॉल्सन ने आर्थिक जोखिमों और यह किसे प्रभावित करते हैं, इसकी व्यापक समझ का उपयोग किया और निम्नलिखित बातें पाईं: <sup>10</sup>

- पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ऐसे जोखिमों का अधिक सामना करना पड़ता है जिनसे बचना मुश्किल होता है।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं को एक साथ कई आर्थिक जोखिमों का सामना करने की अधिक संभावना होती है।
- समय के साथ सभी आर्थिक जोखिमों के प्रति महिलाओं का जोखिम बढ़ा है।
- अधिक जोखिम जोखिम के साथ-साथ कम जोखिम सुरक्षा भी मिलती है, जैसे महिलाओं और उनके परिवारों के लिए पेंशन योजनाएं और जीवन बीमा पॉलिसियां। जो महिलाएं और उनके परिवार आर्थिक जोखिमों का सामना करते हैं, वे जल्दी ही संकट में पड़ सकते हैं।
- उच्च जोखिम वाली महिलाओं के पास कम जोखिम वाली महिलाओं की तुलना में कम बचत होती है।

एकल महिलाओं को एक साथ कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें जोखिमपूर्ण संपत्ति, जोखिमपूर्ण श्रम बाजार की स्थिति और अधिक देखभाल संबंधी जोखिम शामिल हैं। इस अधिक केंद्रित जोखिम जोखिम का मतलब है कि एकल महिलाएं विशेष रूप से अनिश्चित आर्थिक स्थिति में हैं।

एकल महिलाओं को एकल पुरुषों की तुलना में एक साथ कई जोखिमों के संपर्क में आने की तीन गुना अधिक संभावना का सामना करना पड़ता है। तालिका 1 से पता चलता है कि [10,11,12] एकल महिलाओं को इन जोखिमों से अधिक पूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ता है और एकल पुरुषों की तुलना में उनकी कमाई का और भी अधिक हिस्सा खो जाता है: एकल महिलाओं को \$3,453, या 9.3 की तुलना में \$3,552, या उनकी कमाई का 12.7 प्रतिशत खोने की संभावना है। एकल पुरुषों के लिए कमाई का प्रतिशत. महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कई जोखिम जोखिम जल्दी से गायब नहीं होते हैं। आखिरकार, लोग वर्षों और संभवतः दशकों तक अपने परिवार की देखभाल करते हैं, जबकि कभी-कभी उन्हें अपने पूरे करियर के दौरान अनिश्चित श्रम बाजार स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस वास्तविकता के परिणामस्वरूप, महिलाओं और पुरुषों को साल-दर-साल जोखिम जोखिम में अंतर का अनुभव होता है।

हालाँकि, विवाहित महिलाओं को कम संकेंद्रित जोखिम का सामना करना पड़ता है। विवाहित पुरुषों को भी बड़े संभावित नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि वे अधिक पैसा कमाते हैं और उनके पास अधिक संपत्ति होती है। हालाँकि, यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए तलाक और विधवापन के अलग-अलग आर्थिक प्रभाव पर विचार नहीं करता है। "[डब्ल्यू] विधवापन और तलाक के साथ संपत्ति में गिरावट आती है," वेलर और टॉल्सन ने पाया। <sup>11</sup> वास्तव में, रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये गिरावट अधिक है। इसलिए, विवाहित महिलाओं की आर्थिक स्थिरता को अतिरंजित किया जाता है जब यह विचार किया जाता है कि वे विधवापन और तलाक की घटनाओं में पुरुषों की तुलना में असंगत गिरावट का अनुभव करेंगी।

जोखिम के प्रति अधिक जोखिम वाली एकल महिलाओं के पास भी इसके खिलाफ कम सुरक्षा होती है, जैसे कि सेवानिवृत्ति के लिए परिभाषित लाभ पेंशन योजना या आपात स्थिति में उपयोग करने के लिए तरल संपत्ति। उदाहरण के लिए, जिन एकल महिलाओं के पास देखभाल का जोखिम है, उनके पास देखभाल के जोखिम के बिना एकल महिलाओं की तुलना में केवल 3.3 प्रतिशत संपत्ति है। श्रम बाजार जोखिम वाले लोगों के पास केवल 4.7 प्रतिशत संपत्ति है। इसकी तुलना में, बचत जोखिम वाली एकल महिलाओं के पास बचत जोखिम रहित एकल महिलाओं की तुलना में 131.7 प्रतिशत संपत्ति है। तालिका 2 बेरोजगारी जोखिम और देखभाल जोखिम और सुरक्षा के प्रकारों के बीच सहसंबंध दिखाती है जो विशेष रूप से महिलाओं को इन जोखिमों के बोझ से निपटने में मदद करेगी। जबकि विवाहित महिलाओं को बचत सहित अपने जीवनसाथी की जोखिम सुरक्षा तक पहुंच प्राप्त है, एकल महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलता है। परिणामस्वरूप, एकल महिलाओं को न केवल जोखिम अधिक होता है, बल्कि उन्हें इन जोखिमों से सुरक्षा भी कम मिलती है।

नीतियां जो महिलाओं के जोखिम जोखिम को कम करती हैं

आज की अर्थव्यवस्था में जब लोग नियमों के अनुसार खेलते हैं, तब भी वे हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। जैसा कि वेलर और टॉल्सन लिखते हैं, "देखभाल संबंधी जोखिमों को ऐसे माहौल में प्रबंधित करना

कठिन होता है जहां कुछ कर्मचारी देखभालकर्ता के रूप में अपने समय की अप्रत्याशित मांगों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक लाभों का आनंद लेते हैं।<sup>12</sup> और जैसा कि रिपोर्ट में पाया गया है, एकल महिलाओं के लिए इन[13,14,15] जोखिमों का प्रबंधन करना और भी कठिन है, जो अधिक जोखिम जोखिम, कम जोखिम सुरक्षा, और जोखिम के खिलाफ साथी की सुरक्षा तक पहुंच की कमी का सामना करती हैं।

नीतियों को एकल महिलाओं की जरूरतों को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे देश की सबसे बड़ी आबादी में से एक बन गई हैं। जो जोखिम जोखिम को कम करने और जोखिम सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेंगे उनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

- सवैतनिक पारिवारिक एवं चिकित्सा अवकाश और सवैतनिक बीमारी अवकाश।<sup>13</sup> जो लोग देखभाल संबंधी जोखिमों का खामियाजा भुगतते हैं, जैसे कि एकल महिलाएं, उन्हें सवैतनिक पारिवारिक अवकाश और सवैतनिक बीमारी अवकाश की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाले बिना इस जिम्मेदारी को निभा सकें। व्यापक कार्य-जीवन नीतियां लोगों को अपनी और अपने परिवार की देखभाल के लिए आवश्यक समय निकालने में सक्षम बनाएंगी, बिना आय हानि के, जिसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।<sup>14</sup>
- बेहतर बेरोजगारी बीमा. पुरुषों की तुलना में बहुत कम महिलाएं बेरोजगारी बीमा द्वारा सुरक्षित होती हैं और अंततः ऐसी नौकरियों में फंस सकती हैं जो अल्पकालिक स्थिरता प्रदान करती हैं लेकिन कैरियर विकास और आय वृद्धि के अवसर की कमी होती है। बेरोजगारी बीमा का विस्तार और नौकरी चाहने वालों का भत्ता<sup>15</sup> स्थापित करने से महिलाओं को श्रम बाजार जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी।
- सुलभ सेवानिवृत्ति बचत योजनाएँ। बचत योजनाएं, जिनमें सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस एक्शन फंड की प्रस्तावित राष्ट्रीय बचत योजना,<sup>16</sup> जैसी सेवानिवृत्ति बचत योजनाएं शामिल हैं, महिलाओं को - विशेष रूप से एकल महिलाओं को - आर्थिक जोखिमों से निपटने और उनके भविष्य की योजना बनाने में मदद करने के लिए घोंसला अंडे बनाने में मदद करेगी। सीएपी ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की मायआरए योजना का भी समर्थन किया है, जो सभी श्रमिकों के लिए रोथ व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते खोलेगी। इनका उपयोग सेवानिवृत्ति बचत के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर तरल संपत्ति के रूप में किया जा सकता है।<sup>17</sup>

गौरतलब है कि देश की जोखिम सुरक्षा की पुरानी प्रणाली उस बढ़ती कठिनाई को ध्यान में नहीं रखती है जिसका सामना एकल महिलाओं को अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन को एक साथ संतुलित करने में करना पड़ता है। इसके अलावा, जोखिम सुरक्षा की आज की प्रणाली अपरिहार्य जोखिमों से बचाने के लिए वित्तीय सुरक्षा स्थापित करने की एकल महिलाओं की क्षमता को नहीं बढ़ाती है। नीति निर्माताओं को अमेरिकी जोखिम सुरक्षा प्रणाली को फिर से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि यह सभी अमेरिकियों के लिए काम करे। बेहतर उपायों से एकल महिलाओं को उनके सामने आने वाले जोखिमों के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है; इससे उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। बढ़ी हुई सुरक्षा से एक मजबूत अर्थव्यवस्था और समाज बनाने में मदद मिलेगी जिसमें सभी अमेरिकी-विशेषकर एकल महिलाएं शामिल होंगी।

#### विचार-विमर्श

एक महिला के रूप में, आपने संभवतः सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं का सामना किया होगा जो आपकी स्वायत्तता और मूल्य को चुनौती देते हैं। चाहे आप विवाहित हों, अविवाहित हों या तलाकशुदा हों, इन दबावों से निपटना कठिन हो सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, आइए हम पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती देने और अपनी स्वतंत्रता को अपनाने में आपकी ताकत और लचीलेपन का जश्न मनाएं। विशेष रूप से अविवाहित महिलाओं के लिए, यह दिन आपके वित्तीय भाग्य पर नियंत्रण [16,17,18] हासिल करने और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने का अवसर है। यहाँ कुछ वित्तीय सुझाव दिए गए हैं जो अविवाहित महिलाओं को अपने और अपने प्रियजनों के लिए समृद्ध भविष्य बनाने में सशक्त बनाते हैं। भारत में अकेली महिलाओं को वित्तीय समानता की राह पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आय में असमानता बनी रहती है, लिंग आधारित वेतन अंतर के कारण महिलाओं की औसत आय पुरुषों से कम होती है, जिससे आय की संभावना को अधिकतम करने के लिए रणनीतिक वित्तीय योजना बनाना आवश्यक हो जाता है। वित्तीय ज्ञान की कमी इन चुनौतियों को और बढ़ा देती है, क्योंकि कई महिलाओं के पास संसाधनों और शिक्षा तक पहुँच नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक मानदंड और कलंक अक्सर अकेली महिलाओं को अपने वित्त पर नियंत्रण रखने से रोकते हैं, जिससे निर्भरता बनी रहती है और दीर्घकालिक सुरक्षा में बाधा आती है। इन सदियों पुरानी बाधाओं को दूर करने के लिए, आपको रूढ़ियों से मुक्त होने और वित्तीय स्वतंत्रता को अपनाने के लिए एक ठोस प्रयास करना चाहिए, जिससे आपके वित्तीय जीवन में समानता और स्वायत्तता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो। याद रखें, वित्तीय सशक्तिकरण केवल कुछ महिलाओं के लिए नहीं है; यह सभी महिलाओं के लिए है। एक अकेली महिला के रूप में, आपकी वित्तीय योजना आपके वर्तमान और भविष्य दोनों पर केंद्रित होनी चाहिए, और यह यात्रा आज से शुरू होती है। महिलाओं को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले, खर्चों पर नज़र रखने और अपनी आय, निश्चित व्यय और विवेकाधीन व्यय के आधार पर

मासिक बजट बनाने के लिए बजट बनाना आवश्यक है, जिससे बचत और निवेश के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, एक अकेली महिला के रूप में आपातकालीन निधि बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ज़रूरत पड़ने पर परिवार की सुरक्षा न हो। एक मज़बूत आपातकालीन निधि बनाने के लिए, आपको कम से कम छह महीने के जीवन-यापन के खर्चों को एक अलग बचत खाते में अलग रखना चाहिए और अप्रत्याशित खर्चों या अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अंत में, सुनिश्चित करें कि आपके पास आपातकालीन स्थितियों में पैसे के अनावश्यक नुकसान को रोकने के लिए आपके परिवार के सदस्यों, घर, स्वास्थ्य और वाहनों जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाली एक इष्टतम बीमा पॉलिसी है। इन सक्रिय कदमों को उठाकर, अकेली महिलाएं वर्तमान में वित्तीय स्थिरता के लिए एक ठोस आधार बना सकती हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन सक्षम कर सकती हैं। याद रखें, ये कदम सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। अपने रिटायरमेंट की योजना बनाना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है कि आपके पास अपने सुनहरे दौर [19,20,21]में परिवार का सुरक्षा कवच न हो जिस पर आप निर्भर हो सकें। जैसे-जैसे रिटायरमेंट एक अंतिम वास्तविकता बन जाती है, अपनी जीवनशैली को बनाए रखने और काम से छुट्टी लेने के बाद अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय रूप से तैयार होना आवश्यक है। आश्चर्यजनक रूप से, एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 2% महिलाएँ ही रिटायरमेंट के लिए सक्रिय रूप से निवेश कर रही हैं। जल्दी शुरुआत करना और इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे मजबूत रिटर्न वाले विविध परिसंपत्तियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। छोटे निवेश से शुरुआत करके और चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठाकर, आप रिटायरमेंट के लिए एक ठोस वित्तीय कुशन बना सकते हैं। जोखिम कम करने के लिए अपने निवेश में विविधता लाना याद रखें - अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में रखने से बचें। रिटायरमेंट प्लानिंग की दिशा में सक्रिय कदम उठाने से भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति सुनिश्चित होती है। सभी महिलाओं को अपने रिश्ते की स्थिति की परवाह किए बिना रिटायरमेंट प्लानिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन वित्तीय अनिवार्यताओं के अलावा, अपनी वसीयत का मसौदा तैयार करना और उस व्यक्ति या संगठन को नामित करना भी व्यावहारिक है जिसे आप अपनी संपत्ति और सामान छोड़ना चाहते हैं, जिससे किसी अप्रत्याशित घटना के मामले में संभावित कलह और संघर्ष से बचा जा सके। एक बार जब आप इन चरणों को पूरा कर लेंगे, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आपका भविष्य अच्छी तरह से सुरक्षित है। याद रखें, यह सिर्फ अकेली महिलाएँ ही नहीं हैं, बल्कि सभी महिलाओं को वित्त से जुड़ी चीज़ों को समझने, उसके अनुसार योजना बनाने और सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश करने की ज़रूरत है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको जीवन, प्रेम और वित्त की जटिलताओं से गुज़रने वाली एक महिला के रूप में आपकी ताकत, लचीलापन और निहित मूल्य की याद दिलाता है। जैसे-जैसे आप वित्तीय सशक्तीकरण की ओर इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, अपनी वसीयत का मसौदा तैयार करने के लिए समय निकालें, न केवल एक कानूनी औपचारिकता के रूप में, बल्कि अपने प्यार और विरासत की हार्दिक अभिव्यक्ति के रूप में, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी इच्छाओं का सम्मान किया जाए और आपके प्रियजनों को आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक सहायता प्रदान की जाए। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक वित्तीय निर्णय के साथ, आपके द्वारा किए गए प्रत्येक निवेश के साथ, यह जान लें कि आप इस प्रयास में अकेली नहीं हैं। यह सिर्फ अकेली महिलाएँ ही नहीं हैं, बल्कि सभी महिलाएँ हैं जो सफल होने, समृद्ध होने और आशा, संभावना और प्रचुरता से भरे भविष्य को सुरक्षित करने की हकदार हैं।

## परिणाम

वर्ष 2020 महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना जा सकता है। गौरतलब है कि यह महिला अधिकारों और समाज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भूमिका से जुड़ी दो बड़ी घटनाओं की 25वीं वर्षगांठ का वर्ष है। इस वर्ष 'भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति' (CSWI) द्वारा संयुक्त राष्ट्र को 'समानता की ओर' या 'दुवर्द्धस इक्वालिटी' (Towards Equality) नामक रिपोर्ट को प्रस्तुत किये हुए लगभग 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के प्रति संवेदनशील नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंगिक समानता पर एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया गया। साथ ही वर्ष 2020 में 'बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन' की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ भी है, जो समाज में महिलाओं की स्थिति और सरकारों के नेतृत्व में उनके सशक्तीकरण के प्रयासों के विश्लेषण का एक बेंचमार्क है। पिछले दो दशकों में भारत में महिला अधिकारों की रक्षा हेतु कई बड़े प्रयास किये गए और इनके [22,23] व्यापक सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं, हालाँकि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा कर अपेक्षित नीतिगत सुधारों को अपनाना बहुत आवश्यक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका:

- भारत में महिला रोज़गार संबंधी आँकड़े देश के आर्थिक विकास, कम प्रजनन दर और स्कूली शिक्षा की दर में वृद्धि जैसे संकेतकों से मेल नहीं खाती।
- वर्ष 2004 से वर्ष 2018 के बीच स्कूली शिक्षा के मामले में घटते लैंगिक अंतराल के विपरीत कार्य क्षेत्रों में भागीदारी के संदर्भ में लैंगिक अंतराल में भारी वृद्धि देखने को मिली।

- हाल ही में जारी 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), 2018-19' के अनुसार, कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में भारी गिरावट देखने को मिली है।
- वर्ष 2011-19 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 35.8% से घटकर 26.4% ही रह गई।
- वर्ष 2019 में 'विश्व आर्थिक मंच' (World Economic Forum- WEF) की 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और इसके लिये उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में भारत को 153 देशों की सूची में 149 वें स्थान पर रखा गया था।
- गौरतलब है कि इस सर्वेक्षण में भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसमें आर्थिक भागीदारी में लैंगिक अंतराल राजनीतिक लैंगिक अंतराल से अधिक पाया गया।
- वर्ष 2019 में जारी ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार, लिंग के आधार पर वेतन के मामले में होने वाले भेदभाव के मामले में एशिया के देश सबसे प्रमुख हैं, एशिया में समान योग्यता और पद पर कार्य करने वाली महिलाओं को 34% कम वेतन प्राप्त हुआ।
- अक्टूबर 2020 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर 2019 में महिला बेरोज़गारी की दर 9.8% रही जो वर्ष 2019 में जुलाई-सितंबर की तिमाही के आँकड़ों से अधिक है, गौरतलब है कि COVID-19 महामारी के बाद देशभर में बेरोज़गारी के आँकड़ों में व्यापक वृद्धि देखी गई।

असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी:

- कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 60% है परंतु इनमें से अधिकांश भूमिहीन श्रमिक हैं जिन्हें स्वास्थ्य, सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कोई भी सुविधा नहीं प्राप्त होती है।
- वर्ष 2019 में मात्र 13% महिला किसानों के पास अपनी ज़मीन थी और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यह अनुपात मात्र 12.8% था।
- इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र (लगभग पूरी तरह असंगठित) में महिला श्रमिकों की भागीदारी लगभग 14% ही है।
- सेवा क्षेत्र में भी अधिकांश महिलाएँ कम आय वाली नौकरियों तक ही सीमित हैं, 'राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS), 2005' के अनुसार, 4.75 मिलियन घरेलू कामगारों में से 60% से अधिक महिलाएँ हैं।

कारण:

- भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और उससे पहले भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा महिला अधिकारों के मुद्दों को बहुत ही प्रमुखता से आगे रखा गया है।
- देश की स्वतंत्रता के बाद भी महिला अधिकारों और कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में सामाजिक तथा राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहे हैं परंतु देश के विकास के साथ-साथ इस दिशा में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है।
- भारत में कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में कमी के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है।
  - सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि: भारत में लगभग सभी धर्मों और वर्गों के लोगों में लंबे समय से समाज की मुख्यधारा में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को लेकर अधिक स्वीकार्यता नहीं रही है। वर्तमान में भी देश के कई हिस्सों में महिलाओं को घरेलू कामकाज या अध्यापक अथवा नर्स आदि जैसी भूमिकाओं में ही कार्य करने को प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक दबाव और विरोध के भय से कुछ पारंपरिक क्षेत्रों को छोड़कर आमतौर पर अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम ही रही है। भारतीय समाज में व्याप्त इस भेदभाव की शुरुआत बच्चे के जन्म से ही हो जाती है, इस भेदभाव को भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में भारी असमानता [संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund- UNFPA) के अनुमान के अनुसार, लगभग 910] के आधार पर समझा जा सकता है।
  - उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों की कमी: पिछले दो दशकों में देश में प्रारंभिक शिक्षा के मामले में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, हालाँकि उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में कमी अभी भी बनी हुई है। 'अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, 2018-19' की रिपोर्ट [All India Survey on Higher Education (AISHE) report] के अनुसार, प्रौद्योगिकी और तकनीकी से संबंधित पाठ्यक्रमों में नामांकित पुरुष छात्रों (71.1%) की तुलना में महिला छात्रों (28.9%) की भागीदारी काफी कम रही।
  - संसाधनों की कमी: कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी शिक्षा और रोज़गार के अवसरों की उपलब्धता के साथ आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। देश में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों में घर से कार्यस्थल की दूरी, 24 घंटे यातायात के सुरक्षित साधन, सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन या अन्य आवश्यक संसाधनों का न होना और इनकी

वहनीयता भी महिलाओं की भागीदारी में कमी का एक प्रमुख कारण है। इन संसाधनों की अनुपलब्धता का प्रभाव उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर भी पड़ता है।

- कार्यस्थलों पर भेदभाव और शोषण: कार्यस्थलों पर होने वाला भेदभाव महिलाओं के विकास में एक बड़ी बाधा रहा है, देश में सक्रिय सार्वजनिक (सेना, पुलिस आदि) और निजी क्षेत्र के अधिकांश संस्थानों में शीर्ष निर्णायक पदों पर महिला अधिकारियों की कमी इस भेदभाव का एक स्पष्ट प्रमाण है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भूमिका अधिक होने के बावजूद भी समाज के साथ-साथ सरकार की योजनाओं में इसकी स्वीकार्यता की कमी दिखाई देती है। कार्यस्थलों पर भेदभाव और शोषण की घटनाएँ पीड़ित व्यक्ति के साथ आकांक्षी युवाओं के मनोबल को भी कमजोर करती हैं, हाल ही में सोशल मीडिया पर सक्रिय 'मी टू अभियान' (MeToo Movement) के तहत सामने आई महिलाओं के अनुभवों ने इस क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- नीतिगत असफलता: देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सरकार की नीतियाँ अधिक सफल नहीं रही हैं। इसका एक कारण भारतीय राजनीति (लगभग 13% महिला सांसद, स्वतंत्र भारत में मात्र एक महिला प्रधानमंत्री) और नीति निर्माण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी को माना जा सकता है।

महिला भागीदारी का प्रभाव:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत में कार्यक्षेत्र में व्याप्त लैंगिक असमानता को 25% कम कर लिया जाता है तो इससे देश की जीडीपी में 1 ट्रिलियन डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है।
- विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि से कई सामाजिक और आर्थिक लाभ देखने को मिले हैं।
- शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से महिलाओं में अपने स्वास्थ्य तथा विकास के प्रति जागरूकता के बढ़ने के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव समाज तथा देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है।
- देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए बेहतर योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से गरीबी, स्वास्थ्य और आर्थिक अस्थिरता से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

सरकार के प्रयास:

- केंद्र सरकार द्वारा कार्यस्थल पर गर्भवती महिलाओं के हितों की रक्षा के लिये 'मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017' के माध्यम से मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, इस अधिनियम को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित किया गया है।
- विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिये प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 'सर्ब-पावर' (SERB-POWER) नामक एक योजना की शुरुआत की गई है।
- देश में 'मी टू अभियान' के बाद कार्यस्थलों पर बड़े पैमाने पर महिला शोषण के मामलों के सामने आने के बाद अक्टूबर 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (Group of Ministers- GoM) का गठन किया गया, जिसने इस समस्या के समाधान हेतु अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।
- रेल यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा के प्रयासों को मजबूत करने और महिलाओं में सुरक्षा की भावना जगाने के लिये 'रेलवे सुरक्षा बल' (Railway Protection Force-RPF) द्वारा 'मेरी सहेली' (Meri Saheli) नामक एक पहल की शुरुआत की गई है।

चुनौतियाँ:

- भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार, COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण अप्रैल और मई माह में 39% कामकाजी महिलाओं को अपनी नौकरी गँवानी पड़ी।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार, पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं को बिना भुगतान के घरेलू कार्यों में योगदान देना पड़ता है।
- COVID-19 के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई थी, साथ ही इस दौरान महिलाओं के लिये शिक्षा और रोजगार की पहुँच बाधित हुई है जो पिछले कई वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में हुए सुधार के प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।



- भारत में विभिन्न सार्वजनिक (शिक्षा मित्र, आशा कार्यकर्ता आदि) और निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को उनके कार्य के अनुरूप अपेक्षा के अनुरूप कम भुगतान दिया जाना एक बड़ी चुनौती है।
- केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में देश के श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किये गए हैं हालाँकि इनमें देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, कार्यस्थलों पर महिला हितों की रक्षा आदि मुद्दों के संदर्भ में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया है।
- वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ, कार्यस्थलों पर व्याप्त भेदभाव और महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिये बहु-पक्षीय प्रयासों को अपनाया जाना चाहिये।
- सरकार को असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिये लक्षित योजनाओं (प्रशिक्षण, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आदि) के साथ अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा।
- कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये यातायात साधनों की पहुँच में विस्तार के साथ सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन केंद्रों आदि के तंत्र को मज़बूत करना बहुत ही आवश्यक है। [23,24]
- उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षणों में शामिल होने के लिये महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुँच को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही नीति निर्माण और महत्वपूर्ण संसाधनों के शीर्ष तंत्र में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।

#### निष्कर्ष

हम महिलाओं के आर्थिक अवसरों और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। व्यापक शोध से पता चलता है कि जब महिलाएं आय अर्जित करती हैं और अपनी आय पर नियंत्रण रखती हैं, तो उनके बच्चों के स्कूल जाने की संभावना अधिक होती है, उनके परिवार स्वस्थ होते हैं, उनका आत्म-सम्मान बढ़ता है; और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ उनके परिवार की आय भी बढ़ती है।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण टीम, काम में आने वाली बाधाओं को दूर करके, सभ्य कार्य को सक्षम बनाकर, तथा महिलाओं के उद्यमों को समर्थन देकर महिलाओं की शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि महिलाओं और लड़कियों को अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने में मदद मिल सके।

हम बड़ी संख्या में कम आय वाली महिलाओं तक पहुँचने के तरीके खोजते हैं। हम महिला सशक्तिकरण समूहों, डेटा-सूचित सार्वजनिक नीति, डिजिटल कनेक्टिविटी और निजी क्षेत्र की मूल्य श्रृंखलाओं को महिलाओं के आर्थिक समावेशन को आगे बढ़ाने के रास्ते के रूप में देखते हैं। हम ऐसे समावेशी समाधान भी तैयार करते हैं जो महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, वृद्ध ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर युवा शहरी महिलाओं की तुलना में बहुत अलग दिख सकते हैं। हमारी रणनीति दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में कम से कम 80 मिलियन निम्न-आय वाली महिलाओं के लिए अवसर पैदा करने पर केंद्रित है, जिससे 2030 तक उनकी आय में 30% से अधिक की वृद्धि हो सके। हमारी रणनीति का लक्ष्य है:

- उन स्थानों पर महिलाओं को कार्यबल में शामिल करके महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाना जहां महिला श्रम बल भागीदारी कम है
- यदि महिलाएं पहले से ही वेतनभोगी काम कर रही हैं तो उन्हें उच्च-लाभ वाले व्यवसायों में आगे बढ़ने में मदद करके उनकी औसत आय में वृद्धि करना
- महिलाओं को उन परिस्थितियों में कार्यबल में बनाए रखने में सहायता करें, जहां वे आमतौर पर बाहर हो जाती हैं, जैसे कि विवाह के बाद या बच्चे के जन्म के बाद[24]

#### संदर्भ

1. "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill". द हिन्दू. मूल से 25 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2010.
2. ↑ [hindu.com/2010/03/10/stories/2010031050880100.htm "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill"] जाँचें |url= मान (मदद). द हिन्दू. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2010.
3. ↑ Jayapalan (2001). Indian society and social institutions. Atlantic Publishers & Distri. पृ° 145. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9788171569250. मूल से 27 सितंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.



4. ↑ "Women in History". National Resource Center for Women. मूल से 19 जून 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
5. ↑ आदर्श पत्नी: त्रियम्बकयाज्वन द्वारा स्त्रीधर्मपद्धति (महिलाओं के कर्तव्यों में सहायक) (अनुवादक जूलिया लेसली), पेंग्विन 1995 आईएसबीएन 0-14-043598-0.
6. ↑ see extensive excerpts from strIdharmapaddhati at <http://www.cse.iitk.ac.in/~amit/books/tryambakayajvan-1989-perfect-wife-stridharmapaddhati.html>
7. ↑ Mishra, R. C. (2006). Towards Gender Equality. Authorspress. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7273-306-2. मूल से 29 अक्टूबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
8. ↑ Pruthi, Raj Kumar; Rameshwari Devi and Romila Pruthi (2001). Status and Position of Women: In Ancient, Medieval and Modern India. Vedam books. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7594-078-6. मूल से 14 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
9. ↑ कात्यायन द्वारा वर्तिका, 125, 2477
10. ↑ पतंजलि द्वारा अष्टध्यायी के लिए टिप्पणियां 3.3.21 और 4.1.14
11. ↑ आर.सी. मजूमदार और ए.डी. पुसल्कर (संपादक): भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति. वॉल्यूम I, वैदिक युग. मुंबई: भारतीय विद्या भवन 1951, पी.394
12. ↑ "Vedic Women: Loving, Learned, Lucky!". मूल से 20 नवंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
13. ↑ ऊ ए ऐ ओ "InfoChange women: Background & Perspective". मूल से 24 जुलाई 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
14. ↑ <sup>इ</sup> Jyotsana Kamat (2006-1). "Status of Women in Medieval Karnataka". मूल से 1 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006. |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
15. ↑ Vimla Dang (19 जून 1998). "Feudal mindset still dogs women's struggle". The Tribune. मूल से 19 दिसंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
16. ↑ "The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987". मूल से 21 नवंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
17. ↑ K. L. Kamat (19 दिसंबर 2006). "The Yellamma Cult". मूल से 7 जुलाई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 दिसंबर 2006.
18. ↑ दुबोईस, जीन अंटोनी और बौचंप, हेनरी किंग, हिन्दू मैनेर्स, कस्टम्स और सेरेमनिज़, कलेरेंडन प्रेस, 1897
19. ↑ इयान ब्रायंट वेल्स, हिन्दू मुस्लिम यूनिटी का राजदूत
20. ↑ <sup>आ</sup> Jyotsna Kamat (19 दिसंबर 2006). "Gandhi and Status of Women". मूल से 9 दिसंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
21. ↑ "Oxford University's famous south Asian graduates#Indira Gandhi". BBc News. 5 मई 2010. मूल से 19 मई 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (मदद)
22. ↑ <sup>ख</sup> Kalyani Menon-Sen, A. K. Shiva Kumar (2001). "Women in India: How Free? How Equal?". संयुक्त राष्ट्र. मूल से 11 सितंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
23. ↑ Victoria A. Velkoff and Arjun Adlakha (1998). "Women of the World: Women's Health in India" (PDF). U.S. Department of Commerce. मूल से 4 फ़रवरी 2007 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 25 दिसंबर 2006. नामालूम प्राचल |month= की उपेक्षा की गयी (मदद)
24. ↑ "National Policy For The Empowerment Of Women (2001)". मूल से 5 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.



INTERNATIONAL  
STANDARD  
SERIAL  
NUMBER  
INDIA



# International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | [ijarasem@gmail.com](mailto:ijarasem@gmail.com) |

[www.ijarasem.com](http://www.ijarasem.com)